प्रेस विज्ञप्ति

13/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने **11/11/2024** और **12/11/2024** को ओपीजी ग्रुप, चेन्नई के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), **1999** और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विनियमों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने मेसर्स ओपीजी ग्रुप के कार्यालय परिसर और इसके निदेशकों के आवासीय परिसर दोनों से भारतीय मुद्रा में लगभग **8.38** करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

अरविंद गुप्ता द्वारा नियंत्रित ओपीजी समुह, बिजली के विनिर्माण और उत्पादन का व्यवसाय करता है। कंपनी को बिजली क्षेत्र में उपयोग के लिए अरविंद गुप्ता के पारिवारिक सदस्यों द्वारा स्थापित सेशेल्स स्थित कंपनियों से **1,148** करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ था। हालांकि, जांच से पता चला है कि धन का दुरुपयोग किया गया था, और आरबीआई को गलत घोषणा सहित फेमा प्रावधानों के कई उल्लंघन सामने आए हैं।

फेमा, **1999** के प्रावधानों के तहत ईडी की जांच से पता चला कि एफडीआई नीति के तहत कुछ शर्तों के अधीन, बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए लक्षित उक्त एफडीआई फंड का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से शेयर बाजार में लगाया गया था, जिसमें म्यूचुअल फंड में निवेश भी शामिल था और जमीन और रियल एस्टेट में भी निवेश किया गया था, जो एफडीआई दिशानिर्देशों के तहत सख्त वर्जित है। इसके अलावा, विक्रेता कंपनियों की सहायता से एक बड़ी राशि को नकदी में बदल दिया गया, जिसने नकली चालान जारी करने में मदद की, जिससे समूह को भौतिक मुद्रा के रूप में धन निकालने में मदद मिली। तलाशी के दौरान, ईडी ने नकदी के उत्पादन और उपयोग से संबंधित हस्तलिखित नोट भी बरामद किए हैं।

आगे की जांच से पता चला कि ओपीजी समूह के प्रबंधन ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेशेल्स, सिंगापुर और हांगकांग में कई विदेशी संयुक्त उद्यम और कंपनियां स्थापित की थीं, जिनके माध्यम से डायवर्ट किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर विदेश में रखा गया था। इन विदेशी संस्थाओं की जांच की जा रही है ताकि वित्तीय प्रवाह की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या इन फंडों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया था।

एफडीआई के रूप में लाए गए फंड का इस्तेमाल निर्दिष्ट क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। ईडी शेल कंपनियों की संलिप्तता, फर्जी बिल, विदेशी संस्थाओं की संलिप्तता, फंड के डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के संभावित उल्लंघन की भी जांच कर रही है।